

Court No. - 34

Case :- WRIT - A No. - 17963 of 2023

Petitioner :- Gajendra Giri

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Shishir Kumar Dwivedi, Mrityunjay Khare

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Ajit Kumar,J.

1. Heard learned counsel for the parties.
2. Petitioner, who is father of late Shalu Giri claims family pension on account of his married daughter dying in harness on 02.06.2020.
3. The plea taken is that the daughter died within two months of her marriage and even though his son in law was an employed person but the petitioner was solely dependent upon the married daughter having no other independent source of income. He claims that his daughter came into employment as a Constable in Civil Police on 31.05.2019. He does not dispute that he is having a minor son and also another unmarried employed daughter. The other daughter namely Sapna also working as Constable in Civil Police. He, therefore, submits that his claim for terminal dues is valid enough, more especially in the circumstances when his own son in law has given an affidavit in his favour.
4. Learned Standing Counsel on the contrary submits that the petitioner being not solely dependent upon the married daughter as he is already having an unmarried daughter who is employed as Constable in Civil Police, cannot claim to be dependent upon the married daughter who has passed away. Learned Standing Counsel has also drawn the attention of the Court to the Government Order dated 23.12.2016 which entitles the parents of the employees to terminal benefits provided the employee is not survived by widow or widower or issues, as the case may be.
5. Having heard learned counsel for the respective parties and having perused the record, the issue I find needed to be addressed is, whether a mandamus can be issued in the matter where the entitlement of terminal dues to the petitioner is questioned. The

settled legal principle is and so the rule for issuance of writ of mandamus is that an authority must be under obligation to discharge a certain duty under a statute and fails to do so.

6. In the given facts and circumstances of the case and in the light of the Government Order placed before me (annexed as Annexure No. 6 to the writ petition), I find the contention and argument advanced by learned counsel for the petitioner to be holding merit as to the gratuity of the deceased daughter.

7. It is further noticeable that as per the Government Order dated 28.07.1989 in the case of death of an employee the gratuity is to be paid as per the nomination to the members of the family. Clause 2 of the Circular letter dated 11.01.2022 that notices the Government Order is reproduced hereunder:

"2- उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि,

(1) शासनादेश संख्या: 38/2016-सा-3-921 /दस-2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर -7 (4) नई पारिवारिक पेंशन योजना-1965 में यह प्राविधान दिया गया है कि,

वर्ग-1 (क) विधवा / विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र / पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह / पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक। वर्ग-2 (च) अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग -1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह / पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे, हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा / विधुर अथवा बच्चे न हो। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा / विधवा पुत्री की पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित / विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा अश्रित माता पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र उपलब्ध नहीं है तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार उसे ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चों की पात्रता स्थापित होगी।

(2) शासनादेश संख्या: सा-3/1713 / दस-89-933/89 दिनांक 28.07.1989 के प्रस्तर-8 (ख) में यह प्राविधान दिया गया है कि, यदि सरकारी सेवक द्वारा ग्रेच्युटी हेतु नामीनेशन कर दिया गया हो तो ऐसी अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी नामिनेशन के अनुसार ही परिवार के सदस्यों में वितरित की जायेगी किन्तु यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक ने नामीनेशन नहीं किया है तो मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा:-

1- यदि परिवार के निम्न सदस्यों में से एक अथवा अधिक सदस्य जीवित है तो उनमें सम्बन्धिम धनराशि को बराबर-बराबर वितरित कर दिया जायेगा:-

(अ) पत्नी (पुरुष कर्मचारी के मामले में)

(ब) पति (महिला कर्मचारी के मामले में)

(स) पुत्र (सौतेली संतानों तथा गोद ली हुई संतानों को सम्मिलित करते हुए)

(द) अविवाहित पुत्रियों (सौतेली संतानों तथा गोद ली हुई संतानों को सम्मिलित करते

2- यदि उपरलिखित उपखण्ड के अन्तर्गत उल्लिखित परिवार का कोई सदस्य न हो और यदि निम्न सदस्य जीवित हों तो मृत्यु ग्रेच्युटी इनमें बराबर-बराबर बांटी जायेगी:-

(1) विधवा पुत्रियाँ

(2) 18 वर्ष से कम आयु वाले भाई तथा अविवाहित एवं विधवा बहनें (सौतेले भाई व बहन को सम्मिलित करते हुए)

(3) पिता

(4) माता

(5) विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए) तथा

(6) पूर्व मृतक पुत्र की संतानें।"

(emphasis added)

8. Learned counsel for the petitioner submits that his daughter Shalini Giri had nominated her parents in the service records and this has been acknowledged by the Superintendent of Police, Auraiya in the order dated 03.09.2020. The order passed by the Superintendent of Police, Auraiya dated 03.09.2020 is reproduced hereunder:

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद औरैया।

पत्र संख्या:प-25/2020

दिनांक:सितम्बर 3,2020

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा,

औरैया।

कृपया अवगत कराना है, कि कु० शालूगिरी पुत्री श्री गजेन्द्र गिरि नि० लतीफपुर दत्त नगर थाना बोलैनी जनपद बागपत को महिला आरक्षी पुलिस के पद पर जनपद औरैया में दिनांक

17.05.2019 को भर्ती हुई थी। जिसका खाता संख्या: 38489430865 आपकी शाखा में प्रचलित है। पारिवारिक समस्याओं के कारण उक्त महिला आरक्षी द्वारा दिनांक 02.06.2020 को थाना विधूना जनपद औरैया में नियुक्ति के दौरान आत्महत्या कर ली गयी है। खाता खुलवाते समय फार्म में उसने नामिनी कालम में अपनी माता या पिता का नाम आवश्यक अंकित किया था। वर्तमान में उक्त खाते में पड़ी धनराशि को मृतक महिला आरक्षी के आश्रित माता-पिता को भुगतान किये जाने विषयक है। अभिलेखानुसार कु० शालूगिरी की जन्मतिथि 16.03.1998 अंकित है।

अतः स्व० महिला आरक्षी कु० शालूगिरी पुत्री श्री गजेन्द्र गिरि नि० उपरोक्त के खाता संख्या के मूलफार्म की जाँच कराते हुये उक्त खाते में जमा धनराशि को उनके आश्रित माता-पिता के पक्ष में भुगतान कराने का कष्ट करें।

ह० अप०

3/09/20

(सुनीति)

पुलिस अधीक्षक,

औरैया।

(emphasis added)

9. There is no pleading in the writ petition that the gratuity amount as was directed to be paid to the petitioner by the Superintendent of Police, Auraiya in his order addressed to the Branch Manager, State Bank of India, Auraiya has not been released in his favour.

10. In view of the above, I do not find any justification for any direction to be issued for any terminal dues to be paid to the petitioner in the light of Government Order dated 23.12.2016. In so far as the payment of gratuity amount is concerned, whatever is

there in the gratuity account must have been paid to the petitioner in the light of the order passed by Superintendent of Police way back on 03.09.2020 under the Government Order dated 28.07.1989. Hence, I decline to entertain this petition to issue any direction for payment of terminal dues. However, it is clarified that in the event the gratuity amount has remained unpaid despite the order of Superintendent of Police, Auraiya dated 03.09.2020, the same shall be credited into the account of present petitioner and his wife without any further delay.

11. Subject to what has been observed above, this petition is **consigned to records.**

Order Date :- 28.10.2023

IrfanUddin